जे.एल.एन. रोड पर महात्मा गांधी सर्किल पर लगे 4 फाउंटेन भी लंबे समय से बंद

राजधानी जयपुर के इस वीवीआईपी रूट से रोजाना मंत्रियों, अधिकारियों और मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम प्रशासन की लापरवाही और उद्यान शाखा के अफसरों की चहेते ठेकेदारों पर मेहरबानी के कारण राजधानी जयपुर में वी.वी.आई.पी. जवाहरलाल नेहरू रोड स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर लगे चारों फव्वारे लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। यही हाल 39 पार्कों में लगे 42 फव्वारों में से अधिकांश का है। इतना होने के बावजूद भी निगम प्रशासन ठेकेदार के काम की जांच करवाने को तैयार नहीं है। यहां तक फर्म को ना तो कभी नोटिस दिया और ना कोई एक्शन लिया। उल्टा भुगतान के लिए बिल भी पास कर दिया।

हैरानी की बात यह है कि, जेएलएन रोड, राजधानी जयपुर का वीवीआईपी रूट है। यहां से रोजाना मंत्रियों, अधिकारियों और मेहमानों का आना-जाना होता है। परंतु राजधानी की शोभा बढ़ाने वाले ये फव्वारे रखरखाव के अभाव में आज सिर्फ सजावटी ढांचे बनकर रह गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक ठोटर निगम की उद्यान शाखा द्वारा शहर के 39 पार्कों में लगाए गए करीब 42 फव्वारे में से अधिकांश धूल फांक रहे है। पहले तो करोड़ों रुपये खर्च कर इन पार्कों को आधुनिक बनाने और बच्चों को मनोरंजन की सुविधाएँ देने का दावा किया गया था, पर निगम के अफसरों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण इनकी दुर्दशा हो रही है।

जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर लगे चारों फव्वारे लंबे समय से बंद पड़े है।

सूत्रों के मुताबिक, निगम प्रशासन ने फव्वारों के रखरखाव का ठेका गत वर्ष मैसर्स हजारीलाल जसवाल को 70-80 लाख रुपये में दिया था। परंतु ठेकेदार ने वीवीआईपी रूट जे.एल.एन रोड की भी सुध नहीं ली। अन्य पार्कों के फाऊंटेन भी उजाड़ कर रख दिया। इस गंभीर लापरवाही के बावजूद निगम प्रशासन ने न तो ठेकेदार को नोटिस दिया और न ही तकनीकी जांच कराई। इसके विपरीत, अब इस फर्म को पूरा भुगतान करने की तैयारी चल रही है। जबकि इस फर्म को मालवीय नगर जोन में 14, मानसरोवर में 6, सांगानेर में 2, जगतपुरा में 1, झोटवाड़ा में 4, मुरलीपुरा में 9 तथा विद्याधर नगर के 3 पार्कों में फव्वारे का रखरखाव और संचालन करना था। सूत्रों के मुताबिक हैरिटेज नगर निगम ने भी वर्ष 2023 और 2024 में करीब 3 करोड़ से ज्यादा की रकम सभी जोन के पार्कों और जय निवास उद्यान में फाऊंटेन के रख रखाव पर खर्च कर डाले। परंतु वहां भी यह ठेका लेने वाली फर्म ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। इस कारण वहां भी अधिकांश फव्वारे बंद पड़े हैं।

> ■ यही हाल ठोटर निगम के 39 पार्क में लगे 42 फव्वारों में से अधिकांश का है इस धांधली के उजागर होने बावजूद भी उद्यान शाखा, ठेकेदार के काम की जांच करवाने और उसे नोटिस देने को तैयार नहीं है उल्टा भुगतान के लिए बिल भी पास कर दिया

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से की भेंट

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र से अनुदान राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि वे और अधिक समर्पण के साथ अपना कार्य कर सकें।उपमुख्यमंत्री ने राज्य में बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) कार्यालयों की स्वीकृति कराने का आग्रह किया।

''निराश्रित गोवंश मुक्त भारत अभियान''की मुख्य सचिव ने की सराहना

जयपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के क्षेत्र में युगांतकारी कार्य कर रही संस्था ''टीम गौमाया'' की अद्वितीय पहल को आज एक और प्रखर संबल प्राप्त हुआ। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने टीम गौमाया के ''निराश्रित गोवंश मुक्त भारत अभियान'' की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इस पुनीत कार्य में शासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन प्रदान किया।

यह भेंटवार्ता हाल ही में मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को निराश्रित गोवंश के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में हुई। इस अवसर पर ''गोमय परिवार अंशदानी फाउंडेशन'' के संस्थापक, डॉ. सीताराम गुप्ता ने मुख्य सचिव के समक्ष अभियान की विस्तारपूर्वक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी दौरान उन्होंने अपनी गोसंवर्धन पर लिखित एक अनूठी पुस्तक भी मुख्य सचिव को ससम्मान भेंट की। इस पुस्तक की विश्वव्यापी विशेषता यह है कि यह भारतीय नस्ल की गाय के गोबर से बने कागज पर मुद्रित दुनिया की पहली पुस्तक है, जिसे वर्ष 2022 में अमेज़न बेस्ट सेलर के सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है।

इस गरिमामय अवसर पर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ () के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रख्यात समाजसेवी सुरेश पाटोदिया ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने इस अभियान को 'युग की मांग' निरूपित करते हुए इसके सफलतम क्रियान्वयन हेतु अपना पूर्ण समर्पण, संरक्षण एवं सहयोग देने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

3 हजार 200 करोड़ रुपये स्वीकृत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में हर बच्चे को सुलभ, आधुनिक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों से केन्द्र सरकार ने समठा शिक्षा, राजस्थान के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।शर्मा द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समठा शिक्षा, राजस्थान के लिए केन्द्रीय अंश की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समठा शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3 हजार 200 करोड़ रुपये राज्य को देने के लिए सहमति प्रदान की है, साथ ही, इस राशि की प्रथम किस्त शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया है। मुलाकात के दौरान शर्मा ने समठा शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति एवं भविष्य में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी।

बरी होने से पूर्व न्यायिक अभिरक्षा में काटी अवधि का वेतन और परिलाभ देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में कांस्टेबल के दो साल जेल में बंद रहने के बाद बरी होने के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह कांस्टेबल को इस अवधि का वेतन और समस्त परिलाभ अदा करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने इस अवधि को याचिकाकर्ता का अवैतनिक अवकाश मानने के विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है।

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हरभजन सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल को 21 अगस्त, 2000 को दुष्कर्म व एससी,एसटी एक्ट के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं सक्षम अधिकारी ने उसी दिन उसे निलंबित कर दिया।

वहीं अप्रैल, 2021 में उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच भी आरंभ की गई। दूसरी ओर मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र पेश करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर याचिकाकर्ता को एक अगस्त, 2002 को याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। इसी आधार पर विभाग ने 11 सितंबर, 2002 को उसका निलंबन भी रद्द कर दिया।

फिल्म निर्देशक फरहान अखतर को दिया कानूनी नोटिस

जयपुर। एजेएफ अहीर जनजागृति फाउंडेशन के द्वारा फिल्म 120 बहादुर में अहिर समाज के वीरों की शहादत को नजर अंदाज करने पर फिल्म के निर्देशक फरहान अखतर को शहादत का अपमान करने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया है। अहीर जनजागृति फाउंडेशन की राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मंजु यादव ने बताया कि 18 नवबंर 1962 को माइनस 10 डिग्री तापमान में दीपावली की रात भारत-चीन युद्ध में 120 वीर अहीरों की टुकडी चूसूल घाटी में तैनात थी। जैसे ही सेना मुख्यालय द्वारा चीनी सेना के हमले की सूचना पोस्ट कर कहा गया कि आप लोग अपनी जान बचाने के लिए स्वेच्छा से पोस्ट से पिछे हट सकते है।

इसके बाद 120 वीर अहिरों ने मेजर शैतान सिंह को अपने सामूहिक फैसले से अवगत करवाया की वो पोस्ट से पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध लड़ेगे। जब युद्ध लड़ते-लड़ते असला गोला बारूद खत्म होने के पश्चात् वीर अहिरों ने अपनी जान की परवाह किये बिना चीनी सैनिको को बन्दूको के बटों से चाकूओं से चट्टानों से भिड़ाकर व अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाते हुए 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस युद्ध में 120 में से 114 वीर अहिर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय सेना की इस टुकडी के अदम्य साहस को देखकर चीनी सेना द्वारा ब्रेवहर आफ द ब्रेब अहीर नाम से नवाजा गया। दूसरी तरफ फिल्म निर्देशक फरहान अख्तार की कंपनी ऐक्सेल इन्टरटेन्मेंट प्रा. लिमिटेड के बेनर तले बन रही फिल्म 120 बहादुरों में सेना के आधिकारिक रिकॉर्ड से परे युद्व की सच्चाई को छुपाकर तोड़ मरोड़ कर फिल्म बनाई जा रही है। जो वीर शहिदों का अपमान है।

अहीर जनजागृति फाउंडेशन (एजेएफ) की मांग है कि फिल्म 120 बहादुर रिलीज से पहले समाज के प्रबुद्ध जनों के सामने फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएं तथा सेना के रिकॉर्ड में दर्ज इस युद्ध के तथ्यों को निर्देशक फरहान अख्तर पुष्टि करके अपनी फिल्म में बदलाव करके 6 विश्व की महानतम लड़ाइयों में से एक के वीर शहिदों को सम्मान स्वरूप सच्ची श्रद्धांजलि देवे तथा सेना के रिकॉर्ड से 120 वीर शहिदों के फ़ोटो फिल्म की शुरूआत में वर्णन नाम सहित दिखाये जाये।

70 दिन से चल रही पीडब्ल्यूडी संवेदकों की हड़ताल समाप्त

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से गुरूवार को पीडब्ल्यूडी संवेदकों द्वारा लगभग 70 दिन से जारी हड़ताल समाप्त हो गई। आपसी सहमती से तैयार किए गये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद संवेदक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्व होकर काम कर रही है। हमने संवेदकों द्वारा उठाई गई मांगो पर सकारात्मक चर्चा करके उनके सकारात्मक समाधान के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास को प्राथमिक लक्ष्य रखकर हम सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखकर आगे बढ़ रहे हैं।

इससे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता के कक्ष में संवेदक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर उन्हें समझौता पत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यों की निविदाओं में जीएसटी को अलग कर निविदाएं आमंत्रित करने, सीमेंट कंकरीट सड़क निर्माण कार्यों में पीक्यूसी की मोटाई 20 सेमी तक के कार्यों के लिए डीएलपी (गारंटी अवधि) 5 वर्ष रखने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर सहमति बन गई है।इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जिसमे संवेदकों के दो प्रतिनिधि एवं विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि हम सरकार की इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग करेंगे।

खरीदी गई जमीन पर की जा रही बाउण्ड्री वॉल गिराया

उदयपुर। खरीदी गई जमीन पर बनाई जा रही बाउण्ड्री वॉल को जमीन के पीछे के अन्य जमीन मालिकों ने रास्ते की मांग को गिराने का मामला सामने आया है। मदनलाल पुत्र मोतीलाल डांगी निवासी घासा ने रिपोर्ट दी कि मैने ग्राम पंचायत बिठोली में रामचन्द्र पुत्र हिरालाल ब्राम्हाण निवासी विठोली से जमीन खरीदी थी। हमने हमारी जमीन पर बाउंड्री का काम शुरू किया। जिसका काम 5-6 दिन से चल रहा था। 19 अगस्त शाम को लखा पुत्र अमरा, भैरू, देवीलाल पुत्र नारू, उंकार पुत्र नारूलाल निवासी तुरकिया व दो अन्य आए और मजदूरों को काम करने से रोक दिया।